without waiting for the usual invitation of the applications?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BISHMA NARAIN SINGH): (a) The entitlement of an officer for allotment of Government residence is determined on the basis of the emoluments drawn by him and not on the basis of his designations. Government have recently decided to create an *ad-hoc* category for type 'D' accommodation (Type IV) within the range of emoluments of Rs. 500—999 prescribed for type 'C' (Type III) accommodation. Accordingly, those whose emoluments fall within the range of Rs. 700—999 including those awaiting allotment of type 'D' accommodation at the end of the previous allotment year are eligible for type 'D' (type IV) accommodation.

(b) The matter is under consideration.

Flour supplied to Bakery Industry

1900. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the total flour supplied to organised bakery industry in the country, from 1977-78 to 1980-81, year-wise; and

(b) the share of 10 largest bakery units, including Britannia Biscuit and Modern bakery and others separately, in the total, year-wise from 1977-78 to 1980-81?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) and (b). The supply of flour is not controlled by the Central Government and no quantity was allotted to Bakery industry by the Central Government.

रोहिणी योजना के लिए एकत्रित की गई धनराशि का एशियाई खेलों में निवेश

1901. श्री तारिक अनवर :

श्री केशव राव पारधी :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार रोहिणी योजना से प्राप्त होने वाली धनराशि का 1982 में एशियाई खेलों में निवेश करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह राशि केवल रोहिणी आवासीय योजना पर ही खर्च की जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

गोदामों के निर्माण के लिए सहायता

1902. श्री राम लाल राही : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्यान्नों के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम ने उत्तर प्रदेश की उपेक्षा कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;